

इनसाइड



गृहणियों में बढ़ रहा है मेंटल स्ट्रेस, एक्सपर्ट्स ने बताया खुश रहने का तरीका

बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में, द्वंद में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं.

पूरे घर को संभालने वाली (गृहणी/हाउसवाइफ) हमारी मां या पत्नी घर के हर एक सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती हैं. उनका पूरा दिन घर की चार दीवारी में ही शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है. सुबह से रात तक उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी सदस्य को घर में कई तकलीफ न हो. ये सब वो किसके लिए करती हैं? अपने परिवार के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, फिर जब कभी वो जरा गुस्सा हो जाती हैं, तो हम उन्हें गलत समझने लगते हैं. लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो भी कितनी तरह के तनाव से जूझ रही हैं? उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात की है? ओनली माई हेल्थ की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक ऑप्शन होता है. लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में, द्वंद में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं. इस रिपोर्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (Clinical Psychologist) डॉ. प्रज्ञा मलिका (Dr. Pragya Malika) का कहना है कि हाउसवाइफ में तनाव कई वजहों से होता है. ऐसी स्थिति में वे अकेले रहने लग जाती हैं. परिवार में जब कॉन्फ्लिक्ट्स (झगड़े और विवाद) बढ़ते हैं तो वे एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं. जब ये मुद्दे हल नहीं हो पाते तो सुसाइड, तलाक या अन्य मेंटलडिसऑर्डर (Mental Disorder) में बदल जाते हैं. इसे ही दुष्चक्र या विंशियस साइकल (Vicious Cycle) कहते हैं. डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ इन तरीकों को अपनाकर खुश रह सकती हैं.

अपनी हॉबीज को करें याद

डॉ प्रज्ञा का कहना है कि अक्सर महिलाएं घर के काम में उलझकर अपनी हॉबीज (शौक) को भूल जाती हैं. जब ये निराशा या कंटा बढ़ने लग जाए, तो अपने हुनर को याद करें. वो काम जिसे आप पूरे मजे के साथ करते थे, वो दोबारा करें. खुद सोचें कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है. ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेरशानी का कारण ढूँढें

डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें प्रेरशानी किस बात से हो रही है. जब प्रेरशानी की वजह मालूम हो जाए, तब उस पर काम करें. उस प्रेरशानी को मैनेज करें. दरअसल, महिलाओं की टेशन की एक वजह ये भी है कि महिला और पुरुष का दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है. जैसे महिलाएं इमोशनल होकर सोचती हैं और पुरुष लॉजिस्टिक तरीके से सोचते हैं.

नए दोस्त बनाएं

हाउसवाइफ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नए दोस्त बना सकती हैं. अपने घर के आसपास, रिश्तेदारों में या स्कूल-कॉलेज के दोस्तों के संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहना भी कई बार इस स्ट्रेस से निकलने में मदद करता है.

अपने लिए टाइम निकालें

एक हाउसवाइफ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? हाउसवाइफ होने के नाते आपके कुछ सपने होते हैं. तो यहां उन्हें सोचने की जरूरत है कि आप क्या चाहती हैं. खुद को खुश रखने के लिए अपना मी टाइम निकालें.

कुछ चीजों को हालात पर छोड़ दें

डॉ. प्रज्ञा का कहना है कि जिस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकतीं. जो हालात आपके बस से बाहर हैं, तो उन पर न सोचें.

आजादी और आध्यात्मिकता से जीवन हुआ आसान महिलाओं में बढ़ा 'हैप्पीनेस लेवल'

स्टडी में सामने आया कि कम उम्र की युवतियां अपनी लाइफ से ज्यादा संतुष्ट हैं.

अब महिलाओं को मामूली बातों, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बैठना या उठना है, इसके लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. आजादी महिलाओं को खुशी दे रही है.



सर्वे में क्या निकला ?

सर्वे में महिलाओं के साथ बातचीत में सामने आया कि कम उम्र की युवतियां अपनी लाइफ से ज्यादा संतुष्ट हैं. 18 से 40 साल के बीच की कम से कम 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने खुद को खुश बताया. इनमें से ज्यादातर महिलाएं आध्यात्म से भी जुड़ी हुई थीं, यानी पूजा-पाठ या किसी तरह का मेडिटेशन जैसी एक्टिविटी से वो जुड़ी हुई थीं.

आजादी महिलाओं को खुशी दे रही

आपको बता दें कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी महिलाओं में हैप्पीनेस के लेवल को समझने के लिए स्टडी हुई है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा की गई ऐसी ही एक स्टडी के लिए डे रिकंस्ट्रक्शन मथड (Day Reconstruction Method) की मदद ली गई, जिससे ये समझने की कोशिश थी कि एक दिन में महिलाओं के इमोशंस में कितना उतार-चढ़ाव आता है. इसके नतीजों के अनुसार आजादी महिलाओं को खुशी दे रही है.

पुरुषों के मुकाबले बेटर हैं डलर

इस स्टडी में ये भी पाया गया कि फिट रहना भी महिलाओं को ज्यादा खुश रखता है. अध्ययन के मुताबिक एक्सरसाइज करना महिलाओं को उनकी सैलरी मिलने जैसी खुशी देता है. सर्वे में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि अगर महिला और पुरुष को एक जैसी परेशानी दी गई, तो महिला उसे ज्यादा आसानी से डील करती है.

महिलाओं को हो सकती है दिल की बीमारी

कार्डियो वेस्कुलर डिजीज यानी सीवीडी की रोकथाम के बारे में महिलाओं जागरूकता की कमी है. खानपान और लाइफस्टाइल सही नहीं होने से महिलाओं में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. औरतें जिस तनाव का अनुभव करती हैं, अक्सर उनपर आसपास के लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है.

दिल की बीमारी के लक्षण महिलाओं (Women) में उतने स्पष्ट रूप से नहीं नजर आते हैं, जितने पुरुषों में आते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर पुरुषों में को दिल की समस्या होती है, तो एनजाइना जैसे विशिष्ट लक्षण दिख सकते हैं. जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है और सही इलाज और देखभाल शुरू हो सकती है. वहीं महिला में यह समस्या होती है कोई लक्षण नहीं हो दिखते हैं. फिर जब तक बीमारी (Illness) का पता चलता है, ये इतनी गंभीर हो जाती है कि हर तीन में से एक महिला की मौत हृदय रोग के कारण हो जाती है.

जागरूकता की कमी

कार्डियो वेस्कुलर डिजीज यानी सीवीडी की रोकथाम के बारे में महिलाओं जागरूकता की कमी है. खानपान और लाइफस्टाइल सही नहीं होने से महिलाओं में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. औरतें



जिस तनाव का अनुभव करती हैं, अक्सर उनपर आसपास के लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है. इस कारण भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सीवीडी का खतरा बढ़ जाता है. तनाव के साथ, आहार की मात्रा और गुणवत्ता जैसे अन्य कारक भी प्रभाव डालते हैं. इसके अलावा जिन महिलाओं में पॉलीसेस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस, प्रोक्लेम्पसिया, प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और सुगर होती है. उनको हार्ट को लेकर सजग रहना चाहिए.

नियमित जांच

महिलाओं में हृदय स्वास्थ्य लिए नियमित रूप से जांच जरूर करानी चाहिए. कोई लक्षण स्पष्ट रूप से

हो या नहीं यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम का आकलन करने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं. अगर सही समय पर बीमारी का पता चलता है तो महिलाओं में सीवीडी की बेहतर रोकथाम हो सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

जब हार्ट से जुड़ी बीमारी के बारे में पता करना मुश्किल हो, तो ऐसे में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सही रखें महिलाएं अपने खाने में हृदय को स्वस्थ रखने वाली चीजों को शामिल करें जैसे फल सब्जियां, और जिन चीजों में फाइबर ज्यादा हो. उन्हें जरूर अपने आहार में शामिल करें तनाव से दूर रहें.

साफ सफाई से सुधर सकती है महिलाओं की मानसिक सेहत: रिसर्च

शोध में पाया गया है कि सफाई (Cleanliness) आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. अलमारियों पर जमी धूल, किचन को पोंछना या कमरे को व्यवस्थित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए हैं. ये काम मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही फायदेमंद है, जितना मेडिटेशन या योग है. तो अगली बार जब तनाव हो तो घर की सफाई करने से मत कतराइयेगा.



तनाव से निपटने के कुछ लोग योग, माइंडफुलनेस या यहां तक कि स्पा में मालिश लेते हैं ताकि तनाव कम हो. वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अलमारियों पर जमी धूल, किचन को पोंछना या कमरे को व्यवस्थित करते हैं. ये काम उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही फायदेमंद है, जितना लोगों के लिए मेडिटेशन या योग है. तो अगली बार जब तनाव हो तो घर की सफाई करने से मत कतराइयेगा. कुछ लोगों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर तनावमुक्त करने में मदद करता है. सफाई आपके मानसिक स्वास्थ्य कैसे असर करते है आइये जानते हैं.

अव्यवस्था अवसाद में योगदान कर सकती है

“व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान बुलेटिन” में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने अपने रहने की जगह को अव्यवस्थित रखा, उनमें तनाव अधिक पाया गया. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जिन महिलाओं का घर अस्त-व्यस्त रहता है, उनमें कोर्टिसोल का स्तर अधिक होता है. वहीं व्यवस्थित महिलाओं में तनाव कम मिला. इसलिए जरूरी है की घर को व्यवस्थित करना शुरू कर दें.

सफाई और सेहत

शोध में पाया गया है कि सफाई आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. यह मूड में सुधार के साथ-साथ उपलब्धि और संतुष्टि की भावना प्रदान करने के लिए भी है. ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से सफाई आपको तनावमुक्त करने में मदद कर सकती है. तो अपने घर या ऑफिस की डैस्क को साफ करके देखिये तनाव छू मंतर होगा. इसके साथ ही थोड़ी शारीरिक मेहनत भी हो जाएगी जो आपको फिट रखने में मदद करेगी.

इस बात का रखें ध्यान

सफाई करना अच्छी बात है मगर ये हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कई बार लोग सफाई में इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं की दूसरों के घरों में भी डस्टिंग करने लगते हैं. ऐसी अवस्था से बचें.

अपनी बेटियों को करें प्रोत्साहित आत्मविश्वास भरना बेहद आवश्यक

कहते हैं कि बेटियां अपने माता-पिता के लिए बेहद खास होती हैं। जितनी वो खास होती हैं उतनी ही खास उनकी देखभाल भी होती है। जैसे-जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं, वैसे-वैसे उनके प्रति माता-पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। बात अगर पुराने जमाने की करें तो पहले घर-परिवार में बेटियों के पैदा होने पर उन्हें शगुन और साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता था। लेकिन आज के समय में भी बेटियां अपने आत्मविश्वास से ऊंचे से ऊंचा आसमान छूने की प्रतिभा रखती हैं। आज के समय में उनका दर्जा लड़कों से कम नहीं है। ये सब कुछ उनके माता-पिता की परवरिश का नतीजा होता है, जिससे उनका सिर गर्व से ऊपर उठता है। बहुत से माता-पिता होते हैं जो अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हर दिशा में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। यदि आप के घर में भी बेटी है तो आज का ये लेख खास आपके लिए है, जिसके जरिये हम आपको बताएं कि कैसे आप उसकी सही तरीके से परवरिश करें जिससे वो आत्मविश्वास से

भरी रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।

1. **बेटी को करें प्रोत्साहित**—जब बेटी बड़ी होती है, तो उसकी जरूरतें भी अल्प होती चली जाती हैं। आप उसे जमीन से जुड़े अपने भविष्य को लेकर कुछ चुनाव करती है तो उसे हताश ना करें। उसका साथ दें। एक बच्चे के लिए उसके माता-पिता का साथ बेहद जरूरी होता है। आप उसे प्रोत्साहित करें। ताकि उसके अंदर का आत्मविश्वास कम ना हो।

2. **बेटी की करें तारीफ**— आप अपनी बेटी को बताएं की वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। उसके अंदर ऐसी बात है जो उसे बाकियों से जुदा बनाती है। इससे बिटिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा।

3. **सीखने का दें अवसर**— अगर बेटी को संगीत या किसी भी तरह की एक्टिविटी कि कैसे आप उसकी सही तरीके से परवरिश करें जिससे वो आत्मविश्वास से

देगे तो उसका मनोबल टूटता चला जाएगा। उसे सीखने का अवसर जरूर दें। उसे अपनी असल प्रतिभा धीरे-धीरे खुद समझ आएगी और वो आगे बढ़ेगी।

4. **बेटी को सिखाएं समाजिकता**— बेटी को समाज और उससे जुड़ी बातों के बारे में सिखाएं। उसे सिखाएं कि अगर उससे कोई दोस्ती नहीं करता तो उसका क्या कारण हो सकता है। समाज के प्रति उसके अंदर नकारात्मकता ना भरे। वरना एक समय के बाद वो समाज को नकारात्मक नजरिये से देखने लगेगी। उसे सभी पहलुओं के बारे में जरूर सिखाएं।

5. **बढ़ाएं बेटी की क्षमता**— अगर आपकी बेटी अपना होमवर्क कर रही है तो यूं उसकी मदद ना करें। वो जब तक आपसे मदद नहीं मांगती तब तक उसकी मदद मत करें। उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम करने दें। उसे अपने दम में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करें।

6. **ना थोपें अपनी मर्जी**— आज के



समय में बेटियां स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद कर रही हैं, और उसी में अपना भविष्य भी तय कर रही हैं। अगर वो एक जिमनास्टिक बनना चाहती है या फुटबॉल खेलना चाहती है तो उसे आगे बढ़ने दें, ना की अपना फैसला या अपनी चाह उसपर थोपें। आप ये जरूर पता लगा सकते हैं, कि वो किस खेल को खेलने के लिए ज्यादा सक्षम है। आप खुद उसके लिए कोई खेल तय ना करें।

7. **मत बनाइए कमजोर**— आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना

आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना बनाएं। उसकी खूबियों को प्रोत्साहित करने के साथ उसकी कमजोरियों को भी समय पर पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश करें।

देखते या पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई महिलाएं सीनेटरी, खिलाड़ी, चिकित्सक या एथलीट दिखेंगी। ये अच्छा तरीका होता है अपनी बेटी को इन महिलाओं के बारे में दिखाना और समझाना। आप इन्में से कोई भी अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं।

तो ये कुछ ऐसी खास टिप्स हैं, जिनकी मदद से आप अपनी बिटिया को अच्छी परवरिश देने के साथ उसमें आत्मविश्वास भर सकते हैं। अगर आपकी भी बेटी है तो आप हमारी बताई हुई टिप्स को जरूर आजमाएं। आपको इससे बेहतर परिणाम मिलेगा।

प्रदर्शन में बोले केजरीवाल- 'गली-गली में शोर है, भाजपा वोट...', धारा 144 के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में

परिवहन विशेष न्यूज़

चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के चुनाव परिणाम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी है। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने पंजाब और हरियाणा से आ रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर रोक लिया और 25 को हिरासत में ले लिया है।

नई दिल्ली। IAP Protest For Chandigarh Mayor Election: आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के चुनाव परिणाम के खिलाफ आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी है। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने पंजाब और हरियाणा से आ रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिंधु व टीकरी बॉर्डर पर रोक लिया। इसके खिलाफ आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी सौरभ भारद्वाज व तमाम नेता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यहां पहुंचे दिनभर की अपडेट्स...

बीजेपी कार्यकर्ता लिए एग्रेसिव हिरासत में

सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी पूछताछ में शामिल न होने को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसमें शामिल हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जब आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर बढ़े तो बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल द्वारा बैरिकेड्स पर रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़ कर आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर दौड़े तो उन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक लिया और हिरासत में लेकर इन्द्रप्रस्थ स्टेट थाने ले गई।

बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े केजरीवाल और भगवंत मान



सीएम केजरीवाल और भगवंत मान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बीजेपी पार्टी मुख्यालय की तरफ निकल गए। इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती की गई। पुलिस ने कहा कि आप का प्रदर्शन गैरकानूनी है, तुरंत बंद कर दें। सड़क को खाली कर दें।

बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है:

केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ₹ अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा चुनाव गड़बड़ करके जीतती है। हम सुना करते थे कि भाजपा फर्जी वोट पड़वाती है लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके (भाजपा) पाप का घड़ा भर गया था। जब

पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है।

केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे आप दफ्तर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आप दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव जीत गए तो इनका नाम नरेंद्र पुतिन हो जाएगा। वहीं भगवंत मान ने कहा कि अगर गड़बड़ी ही करनी है तो चुनाव क्यों करते हो, तानाशाही शुरू कर दो।

विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी मेयर नजरबंद

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल को घर में नजरबंद रखा गया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है।

पार्टी दफ्तरों में मल्टीलेयर बैरिकेडिंग

पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली में मल्टीलेयर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा

बढ़ा दी गई है। जहां आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, वहीं भाजपा ने कहा है कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे।

'देश जानता है भाजपा ने की धोखाधड़ी'

आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि 'देश जानता है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धोखाधड़ी की। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज बीजेपी कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन से पहले, हमारे विधायकों, पापों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर हिरासत में लिया जा रहा है। क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इतनी डरी हुई है कि वे यह विरोध प्रदर्शन नहीं होने दे रहे हैं?'

टीकरी बॉर्डर पर भी रोके जा रहे कार्यकर्ता

टीकरी बॉर्डर पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हालांकि यहां पर आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। ज्यादातर लोग बहादुरगढ़ से मेट्रो में सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्हें कैसे रोका जाए।

पुलिसकर्मियों का कहना है कि सिर्फ उन लोगों को रोका जा रहा है जो गाड़ी पर या तो झंडा लगाकर आ रहे हैं या उन्होंने गाड़ी पर कोई बैनर लगाया हुआ है।

पहले वोट चोरी किए अब...

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक केजरीवाल का दावा है कि पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग कर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए। अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह-जगह दिल्लीभर में रोका जा रहा है।

'हमें तो मौका ही नहीं मिला, कोर्ट का जल्दबाजी में आया फैसला', ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान



ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हो रही है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जमीयत उलेमा ए हिंद के मुख्यालय में हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हुआ इससे मुस्लिमों के साथ अमन पसंद लोगों को धक्का पहुंचा। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी राय रखी।

नई दिल्ली। ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हो रही है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जमीयत उलेमा ए हिंद के मुख्यालय में हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हुआ, इससे मुस्लिमों के साथ अमन पसंद लोगों को धक्का पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह इतिहास गढ़ा गया, कोर्ट ने जल्दबाजी में निर्णय दिया। दूसरे को कहने का मौका नहीं दिया। इससे ईसाफ पसंद लोगों के भरोसे पर चोट पहुंची है। बाबरी मस्जिद में भी कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं थी, लेकिन आस्था को देखकर एक पक्ष में फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी फैसले पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति से भी मिलने को समय मांगेंगे।

फैसला देने में कोर्ट में लचिलापन: मदनी

वहीं दारुल उलूम देवबंद के वर्तमान प्राचार्य अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान मुल्क की आजादी के बाद इस तरह की मसाल में घिरा हुआ है। मथुरा, संभल, ज्ञानवापी और बाबरी जैसे मस्जिद के मामले उठते रहे, लेकिन अब जिस तरह से ये मसाल उठे हैं, उससे महसूस होता है कि कानून के आलोक में न्याय देने वाले कोर्ट में लचक और ढील पैदा हुई है, जो इबादतगाहों पर कब्जे में सहूलियत मिली है। उन्होंने कहा कि बाबरी ने जो रास्ता खोला कि धर्म आधारित मुकाबला होगा तो फैसला कानून आधार पर नहीं हो रहा। यह लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। इन तमाम कानूनी किताबों पर आग लगाओ। मुल्क इससे नहीं चलेगा। इसकी जद में जैन बौद्ध, ईसाई भी आएंगे।

एक्टर फा फैसले के बाद हम कहाँ जाएं:

मदनी

महमूद मदनी ने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया चिन्ह लग गया है। जिस तरह से एक तरफा तरीके से जाते जाते जज ने इस तर्क का फैसला दे दिया, फिर ऊपर की अदालतें तकनीकी कारणों से दखल देने को तैयार नहीं तो दूसरा पक्ष कहाँ जाएगा। ऐसी परिस्थिति है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या न करें। बात इस तलक न जाएं की खराबी तक चला जाए, बड़े संघर्ष से आजादी मिले है।

टेंट हाउस के गोदाम में चोरी कर रहे युवक को पीट-पीटकर मार डाला

वह विनोद के साथ 27 जनवरी की रात को एक टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने के लिए गया था। वह चोरी कर ही रहे थे कि गोदाम के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। वह तो किसी तरह से वहां से भाग निकला विनोद को उन्होंने छोड़ा नहीं। पुलिस ने टेंट हाउस पर छापेमारी कर आफताब को गिरफ्तार किया है।



पूर्वी दिल्ली। ज्योति नगर इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने गए युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। उसके शव को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर स्थित सुरना गांव में ठीकाने लगा दिया। हत्या के पांच दिन के बाद पुलिस ने विनोद बहादुर के शव को गांव की झाड़ियों से बरामद कर लिया है।

अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस

पुलिस ने टेंट हाउस के कर्मचारी आफताब को गिरफ्तार किया है। उसे रिमांड पर लेकर पुलिस उसके साथियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अगवा व हत्या की धारा में प्राथमिकी की है। विनोद बहादुर परिवार के साथ हरदेव पुरी गली नंबर-4 में रहता था। परिवार में मां व अन्य सदस्य हैं। विनोद की मां सारा ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि 27 जनवरी की रात को उनके बेटे को आखिरी बार ईस्ट लोनी रोड स्थित जल बोर्ड के कार्यालय के पास देखा गया था।

टेंट हाउस गोदाम में चोरी करने गया था

वह घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीएसआर के तहत किया सफदरजंग अस्पताल का सहयोग

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सीएसआर फंड के तहत सफदरजंग अस्पताल को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। यह सीएसआर प्रोग्राम सफदरजंग अस्पताल के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा। बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हुए उदारतापूर्वक इन्फ्र यूजन पंप, व्हीलचेयर, वॉकर, कर्मोड चेयर और बैसाखी जैसे उपकरणों की सहायता प्रदान की।

बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक, राकेश शर्मा और उप महाप्रबंधक, श्री निशार्थि द्वारा ये सहायता सफदरजंग अस्पताल को उपलब्ध करवाई गई।

इन्फ्रयूजन पंप रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जबकि गतिशील सहायता, व्हीलचेयर, वॉकर, कर्मोड कुर्सियां और बैसाखी रोगियों के मुख्य धारा में लाने का कार्य करेंगी।

यह भव्य सहायता कार्यक्रम सफदरजंग अस्पताल की अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने बैंक के उदार समर्थन



के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी को मजबूती से पूरा करना बैंक की समुदाय के प्रति स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर राकेश शर्मा ने कहा कि रसूल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मिशन में सफदरजंग अस्पताल के साथ साझेदारी करके हमें खुशी हो रही है। यह पहल उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डीएसआर लक्ष्यों के अनुरूप है।

बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित है और

समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यह पहल उन समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच पर स्थायी और सार्थक प्रभाव डालने की बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सफदरजंग अस्पताल में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई निर्मित शाखा का रिबन काटने का समारोह अतिरिक्त एमएस डॉ. पीएस भाटिया, अतिरिक्त एमएस डॉ. जयंती मणि, डॉ. नीरज गुप्ता, सीएसआर टीम और श्री की उपस्थिति में प्रोफेसर डॉ. वंदना तलवार चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया। रोहित चौधरी मुख्य महाप्रबंधक भी इस मौके पर मौजूद रहे।

पार्टी के 7 विधायकों के संपर्क में है और 25 करोड़ रुपये देने की बात भी कह रही है। यह आरोप केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया था।

क्राइम ब्रांच के घेरे में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम के घर पहुंची एक टीम; जानिए क्या है मामला

परिवहन विशेष न्यूज़

नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम आप विधायकों के खरीदने की कोशिश से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल के घर गई थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के घर पर न मिलने से वापस लौट आई है।

आप ने भाजपा पर लगाया था ये आरोप

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के संपर्क में है और 25 करोड़ रुपये देने की बात भी कह रही है। यह आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया था।

भाजपा ने आरोपों पर मांगे साक्ष्य

इसके बाद भाजपा ने दिल्ली पुलिस में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा के अन्य पदाधिकारी, सांसद व विधायक दिल्ली पुलिस आवृत्त संजय अरोड़ा से मिलकर लिखित शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली



सरकार की मंत्री आतिशी, विधायक हर्षेश पाठक व दिलीप पांडे पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शनिवार को फिर जाएगी टीम

साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री के आरोप को तथ्यहीन बताते हुए उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि टीम सीएम से जांच में लगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली

ED की पूछताछ में केजरीवाल के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने CM पर बोला हमला, कहा- पापों का होगा हिसाब

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी की जांच में शामिल न होने पर दिल्ली बीजेपी ने जांच से भागने का आरोप लगाया है। भाजपा की प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को अवैध बता रहे हैं तो फिर उन्हें न्यायालय का रुख क्यों अभी तक नहीं किया है? वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने भी जमकर हमला बोला है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी की जांच में शामिल न होने पर दिल्ली बीजेपी ने जांच से भागने का आरोप लगाया है। भाजपा की प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को अवैध बता रहे हैं तो फिर उन्हें न्यायालय का रुख क्यों अभी तक नहीं किया है? उन्होंने कहा कि देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति और मुख्यमंत्री को समान अधिकार देता है, इसलिए यह अरविंद केजरीवाल के

अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना समन अवैध है या गैर कानूनी है। इसके लिए अदालत में जाना चाहिए।

कई नेताओं को जमानत नहीं मिल रही: बांसुरी

स्वराज ने कहा कि केजरीवाल को शोभा नहीं देता कि सीएम होने के बाद भी जांच से भागने का वह बार-बार प्रयास कर रहे हैं। शराब घोटाले में कोर्ट ने कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपये पिछले दरवाजे से वापस लिए हैं। इस देश की विभिन्न अदालत भ्रष्टाचार में लिप्त आप

नेताओं को जमानत नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

पापों का होगा हिसाब: कपिल मिश्रा

वहीं, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। वह कितना भी भागे उनके चोरी और पापों का हिसाब होगा। इसके इतर भाजपा ने आप कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के प्रदर्शन के हॉर्डिंग्स फाड़ने पर आप की बोखलाहट करार दिया है।

बिक्री के लिए उपलब्ध है क्वीन एलिजाबेथ की कस्टम रेंज रोवर, शाही एसयूवी के लिए रखी इतनों पैसों की मांग

नई दिल्ली। Queen Elizabeth II की Range Rover बिक्री के लिए उपलब्ध है। कभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पसंद रही इस पॉपुलर एसयूवी को वर्तमान में ब्रैमली नीलामीकर्ताओं के माध्यम से लॉयर ब्लू रंग में सेल किया जा रहा है। इसकी कीमत 379,850 यूरो (लगभग 4,01,41,712 रुपये) रखी गई है। आइए जान लेते हैं कि ये कीमत कितनी खास है।

Queen Elizabeth II की Range Rover

ब्रैमली मोटर कार्स की आधिकारिक वेबसाइट पर Queen Elizabeth II की Range Rover के बारे में सभी डिटेल्स साझा की हैं। इस कार को शाही उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसके इंटीरियर में शानदार ब्लैक लेदर और ब्लैक बैज कार्बन फाइबर ट्रिम के साथ जोड़ा गया ब्लैक डायमंड फिनिश है। इसकी तस्वीरें भी साझा की गई हैं-

इसके अलावा ये कार शूटिंग स्टार हेडलाइनर, मसाज सीट्स और ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम से लैस है। आइए, इसकी अन्य खासियत के बारे में क्रमवार जान लेते हैं-

इस एसयूवी का मूल पंजीकरण नंबर अभी भी OU16 XVH है।

ये अभी तक केवल 18,000 मील ही चली है।

इसे मार्च 2024 तक किसी सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है।

इसकी कीमत 379,850 यूरो (लगभग 4,01,41,712 रुपये) रखी गई है।



क्या Paytm FASTag 29 फरवरी के बाद नहीं करेगा काम ? सभी सवालों के जवाब जो दूर करेंगे आपकी उलझन



Paytm FASTag

29 फरवरी के बाद होगा बंद?

RBI ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला लेते हुए PPBL की बैंकिंग सेवा पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट के लिए डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही प्रीपेड कार्ड फास्टैग एनसीएमसी कार्ड आदि में डिपॉजिट क्रेडिट लेनदेन टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी क्या आपको फास्टैग भी काम नहीं करेगा।

आइये जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं।

नई दिल्ली। RBI ने पेटीएम और इसके कस्टमर्स को चौकाते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साथ वॉलेट और कुछ अन्य सर्विसेज को भी बैंक कर दिया है, जिसमें पेटीएम फास्टैग भी शामिल है। इसके चलते आप अपने फास्टैग में डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन, टॉप-अप नहीं कर सकेंगे।

ऐसे में ज्यादातर लोगों के बीच से इस सवाल ने जगह बना ली है कि क्या वो 29 फरवरी के बाद अपने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं।

क्या है बैंक का कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अपने अधिकार के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए कस्टमर्स को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है।

RBI ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या कर सकते हैं कस्टमर्स

कंपनी ने अपनी X पोस्ट के जरिए बताया

की अगस्त 2023 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में FASTag का सबसे बड़ा इशूअर रहा है। इसके साथ लोग 300 से अधिक शहरों में टोल का भुगतान करें।

कंपनी ने बताया कि फास्टैग और NCMC कार्ड में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग, निकासी या ट्रांसफर 29 फरवरी तक पहले जैसा ही किया जा सकता है। हालांकि इन अकाउंट में किसी भी टॉप अप या आगे क्रेडिट की अनुमति केवल 29 फरवरी, 2024 तक ही है।

ऐसे में एक निश्चित समय के बाद ही सही Paytm FASTag यूजर्स को अपना FASTag बंद करना होगा और यहाँ तक कि अपने वाहन को भी इससे अलग करना होगा।

Ola S1 X 4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.10 लाख रुपये की कीमत में हुआ लॉन्च

Ola S1 X 4kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च हो गया है। इसको किफायती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर में S1 X लाइनअप का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगल चार्जिंग में लंबी रेंज देने का वादा करता है। यह S1 X 3 kWh वैरिएंट से लगभग 20000 रुपये अधिक महंगा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। Ola Electric ने हाल ही में S1 X 4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर वैरिएंट को लॉन्च किया है। इसको किफायती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर में S1 X लाइनअप का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगल चार्जिंग में लंबी रेंज देने का वादा करता है। यहां इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

Ola S1 X 4 kWh की कीमत

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.10 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। यह S1 X 3

kWh वैरिएंट से लगभग 20,000 रुपये अधिक महंगा है। जबकि एंट्री लेवल Ola S1 X 2 kWh ट्रिम की कीमत 79,999 रुपये एक्स शोरूम है।

फीचर्स और मोड

Ola S1 X 4 kWh में S1 X 3 kWh वैरिएंट के समान ही मैकेनिकल फीचर्स बरकरार रखे गए हैं। यह महज 3.3 सेकंड में ही 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 90 किमी/प्रति घंटा है। इलेक्ट्रिक मोटर 6 फिलोवाट 8bhp का उत्पादन जारी रखती है। इसमें तीन राइडिंग मोड प्रदान किए गए हैं जो कि ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट हैं।

अप्रैल में शुरू होगी डिलीवरी

स्कूटर लॉन्च के दौरान कंपनी ने इसकी डिलीवरी के बारे में भी जानकारी दी है। कंपनी ने पुष्टि की कि S1 X 2 kWh और 3 kWh वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2024 से शुरू होगी। वहीं, नए S1 X 4 kWh वैरिएंट की डिलीवरी भी अप्रैल में शुरू होगी, इसके टॉप वैरिएंट के लिए कंपनी मौजूदा वक्त में बुकिंग स्वीकार कर रही है।

महिंद्रा स्कोर्पियो एन, थार और एक्सयूवी 700 की कीमतों में हुई 57 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी, यहां देखिए नए प्राइस

Mahindra Mahindra की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी XUV700 SUV पर लागू की गई है। 7-सीट कॉन्फिगरेशन और मैनुअल गियरबॉक्स वाले AX7 L पेट्रोल वैरिएंट में 57000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया डीजल वैरिएंट अब 53000 रुपये तक महंगा हो गया है। आइए अपडेटेड प्राइस लिस्ट के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Mahindra ने इस हफ्ते से अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Scorpio-N, Thar और XUV700 को महंगा कर दिया है। कार निर्माता ने तीन एसयूवी के कुछ वैरिएंट पर तत्काल प्रभाव से नवीनतम मूल्य वृद्धि लागू कर दी है। बढ़ती उत्पादन लागत के कारण इस महीने से उसके वाहनों की कीमत अधिक हो जाएगी। ताजा बढ़ोतरी में इन गाड़ियों की कीमत 57,000 रुपये तक बढ़ गई है।

Mahindra XUV700 की नई कीमतें

Mahindra & Mahindra की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी XUV700 SUV पर लागू की गई है। 7-सीट कॉन्फिगरेशन और मैनुअल

गियरबॉक्स वाले AX7 L पेट्रोल वैरिएंट में 57,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया डीजल वैरिएंट अब 53,000 रुपये तक महंगा हो गया है।

दिलचस्प बात यह है कि नवीनतम अपडेट में एसयूवी के आठ वैरिएंट की कीमतों में भी कमी देखी गई है। पेट्रोल के चार एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमतों में 15,000 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 5-सीट विकल्पों के साथ पेश किए गए AX5 डीजल वैरिएंट पर 21,000 रुपये की सबसे बड़ी कीमत में गिरावट लागू की गई है।

XUV700 की कीमत अब 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 26.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसके सात वैरिएंट्स की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

Mahindra Scorpio-N की नई कीमतें

स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल की कीमतों में भी 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। दोनों एसयूवी के सभी वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो एक को छोड़कर, कम से कम 1,000 रुपये से शुरू होती है।

AWD और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ Z8 7-सीटर वैरिएंट की कीमत, जो 23.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में बेची जाती है, अपरिवर्तित बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों संस्करणों में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ Z8 L 6-सीटर पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है।

जहां पेट्रोल स्कॉर्पियो-एन के एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत में 34,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं एंट्री-लेवल डीजल वैरिएंट की कीमत में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। स्कॉर्पियो-एन एसयूवी अब 13.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आती है और टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 24.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Mahindra Thar की नई कीमतें

Mahindra Thar एसयूवी के सभी वैरिएंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा AX(O) डीजल मैनुअल वैरिएंट पर 35,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ लागू की गई है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले टॉप-एंड पेट्रोल वैरिएंट LX की कीमत भी 34,000 रुपये अधिक होगी। थार एसयूवी की कीमत अब 11.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 17.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

विपक्षी गठबंधन में दरारें

दरअसल विपक्ष में भी एक पक्ष था और दूसरा विपक्ष था। यह इंडी गठबन्धन बनते समय ही दिखाई दे रहा था। क्षेत्रीय दल कांग्रेस को खाकर अपना वजन बढ़ाना चाहते थे और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को डकार कर अपना वजन बढ़ाना चाहती थी। यह ठीक है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लगभग बिखर गई है। यदि केवल सांसदों की संख्या के बल पर ही किसी दल का आकलन करना हो तो उसकी स्थिति भी लगभग किसी बड़े क्षेत्रीय दल के समान ही है। वैसे भी देश के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल मोटे तौर पर कांग्रेस को हाशिए पर धकेल कर ही पैदा हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक और तथ्य भी है। बिखरी हुई कांग्रेस का मलबा लगभग सभी राज्यों में इधर-उधर बिखरा पड़ा है। कांग्रेस की इच्छा है कि किसी तरह इस मलबा से फिर से, कम से कम छोटा भवन पुनः बना लिया जाए। बाद में समय मिलने पर उसका विस्तार किया जा सकेगा।

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

मुझे नहीं लगता
मल्लिकार्जुन खडगे
की अहमियत
पोस्टर से ज्यादा हो।
अलबत्ता उनका
काम राहुल गांधी की
स्वयं को ही
नुकसान देने वाली
उक्तियों की
सकारात्मक
व्याख्या कर देने भर
तक सीमित हो गया।
मोदी के खिलाफ
विपक्ष एकजुट नहीं
हो पा रहा है। वह
बिखर चुका है•

पैर रखने को जगह मिल जाए तो सिर छुपाने का जुगाड़ भी कर लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो चतुर मिस्त्री/शिल्पी चाहिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज परिवार के पास इस समय वह नहीं है। राहुल गान्धी को जबरदस्ती मिस्त्री का काम करने के लिए धकेला जा रहा है, लेकिन राहुल इसमें सफल हो नहीं रहे। जहां सीमेंट लगाना है, वहां ईंट लगा देते हैं, जहां लकड़ी का काम करना है, वहां शीशा लगाने लगते हैं। अब उनकी सहायता के लिए एक बुजुर्ग मल्लिकार्जुन को भी साथ लगाया गया है। वे बेचारे राहुल को लेकर गली गली घूम रहे हैं। उधर पार्टी चिल्ला रही है, बाबा सिर पर चुनार है, आप दोनों किस काम में लगे हुए होस लेकिन कोई सुने तब न। राहुल मस्त हैं। बंगाल में हलकान हो रहे हैं। बंगालियों, यदि इस बार भी न जागे तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्षेत्रीय दलों का मसला दूसरी तरह का है। उनको कांग्रेस से भय नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस अब उनके इलाके में दाखिल नहीं हो सकती। उनकी चिंता भाजपा से है। भाजपा ने जिस प्रकार उत्तरी भारत में जनता को लगभग साथ ले लिया है, उससे उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वे चाहते हैं कि



उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस उनकी मदद करे। जाहिर है कि यदि कांग्रेस मदद करेगी तो बदले में भी कुछ चाहेगी ही। लेकिन क्षेत्रीय दल उसे वह 'कुछ' देने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता यह जरूर कह रहे हैं कि अपने इलाके को छोड़ कर सारे हिंदुस्तान में वे कांग्रेस की मदद करने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में हम अकेले भी लड़ लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस से मिल कर लड़ेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की रोटी में से एक टुकड़ा आम आदमी पार्टी को दे दे, लेकिन पंजाब में उससे रोटी में हिस्सा न मांगें। इस प्रकार हर प्रदेश में टुकड़ा-टुकड़ा रोटी का इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी पैन इंडिया पार्टी बनना चाहती है, लेकिन बदले में देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। जहां पंजाब में है, वहां उसकी इच्छा है कि कांग्रेस इस इलाके से दूर ही रहे। यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। यही समता कर रही है। साम्यवादियों के पास अब देने-लेने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए वे कांग्रेस के शरीर में घुस कर अंदर से कब्जा करना चाहते हैं। शरीर बाहर से कांग्रेस का ही दिखाई देता रहे, लेकिन अन्दर आत्मा कम्युनिस्टों की कब्जा कर ले। वैसे वे यह प्रयोग पिछले लम्बे अरसे से कर रहे हैं। अबकी बार उनका अपना अस्तित्व ही इस प्रयोग के सफल होने पर निर्भर है। इस प्रयोग की सफलता के लिए वे वामगामी हरकतों पर उतर आए हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि जब भी इंडी गठबंधन की मीटिंग होती है तो उसका नियंत्रण सीता राम येचुरी ही करते लगते हैं। इसी निराकार हालत को देख कर नीतीश बाबू ने एक और प्रयोग कर लेना चाहा। बिहार की राजनीति में वे धीरे-धीरे सिकुड़ते जा रहे थे।

लालू का कुनबा और काम दोनों बढ़ते जा रहे थे। इस स्थिति में या तो लालू नीतीश बाबू को राजनीतिक तौर पर खा जाएँ या फिर वे स्वतः ही प्रदेश की राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। प्रदेश की राजनीति में वे चढ़ाव से उतार वाली स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। नीतीश बाबू संकट का उपयोग भी लाभदायक ढंग से करने में होशियार माने जाते हैं। उनको लगा यदि सभी विरोधी दलों को एक साथ बिठा लिया जाए और चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा आ जाए तो सम्भावनाओं के अपार द्वार खुल सकते हैं। भारतीय राजनीति में इस प्रकार की स्थिति पहले भी पैदा हो चुकी थी। उसी स्थिति में से देवेगौड़ा, चन्द्रशेखर, इन्द्र कुमार गुजराल, चरण सिंह तक प्रधानमंत्री बन गए थे। बस इस प्रकार की हालत में आपको पार्टी के पास 25-30 सांसद होने चाहिए। इसका एक ही रास्ता नीतीश बाबू को दिखाई दिया। यदि नीतीश और लालू दोनों मिल जाएं तो बिहार में तीस-पैंतीस सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। लालू को प्रधानमंत्री बनने की अब इस उध्र में सेहत के कारण तमन्ना नहीं है। लालू पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री। लालू को भी यह सौदा बुग्रा नहीं लगा। नीतीश बाबू जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी के सिर पर रख कर दिल्ली चले जाएंगे। नीतीश बाबू भाजपा के एनडीए से निकल कर लालू के साथ चले गए और कांग्रेस व कम्युनिस्टों के साथ लेकर महागठबन्धन बना लिया। सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए दौड़-धूप भी शुरू कर दी। लालू भी अपने बच्चों सहित आगे-आगे चलने लगे। उनके दोनों हाथ घी में। नीतीश प्रधानमंत्री बनें या न बनें, उनका अपना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी चार महीनों के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड छठा बजट है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया और अर्थव्यवस्था, विकास की हरी-हरी तस्वीर पेश की गई। मसलन-भारत विश्व-गुरु के तौर पर उभर रहा है। जनता खुश है और सशक्त हुई है। उसमें उम्मीद और आशावाद जागा है। सरकार के 10 सालों में सकारात्मक अर्थव्यवस्था रही है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक समावेश का आर्थिक विकास हुआ है। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है। भारत 2047 में 'विकसित राष्ट्र' होगा। अंतरिम बजट से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को आम चुनाव जीतने की कोई चिंता नहीं है, लिहाजा वित्त मंत्री ने दावा किया है कि जुलाई के पूर्ण और आम बजट में विकसित भारत के व्यापक विकास का रोड-मैप पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में किसी महत्त्वपूर्ण और नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही आयकर-व्यवस्था में कोई बदलाव किया गया है। फिर भी कुछ घोषणाएँ ऐसी हैं, जो मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार हैं, लेकिन उनमें लोकलुभावन भाव भी निहित है। सरकार ने आगामी 5 साल में 2 करोड़ पक्के घर बनाने की घोषणा की है, जबकि 3 करोड़ घर बनाने का दावा किया गया है। अंतरिम बजट में 5 साल की योजना की घोषणा की प्रासंगिकता कितनी है ? जाहिर है कि भाजपा आगामी सत्ता को लेकर भी आश्वस्त है। प्रधानमंत्री मोदी के रहमों-कम पर सिमट गए। इसलिए उन्होंने इस चौथ में दरी से उठ जाना ही बेहतर समझा। ममता अभी तक बैठी तो दरी पर ही हैं, लेकिन वहीं बैठे-बैठे दूसरे दरीवानों को धमका रही हैं कि खबरदार किसी ने मेरी थाली की ओर आंख उठा कर भी देखा। मीडिया इसी को इंडी का बिखराव कहता है।

लक्ष्य तय किया गया है। यह मोदी सरकार की 'महिला सशक्तिकरण' की राजनीति को स्तम्भापित करती है। सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी-मुक्त किया गया है और यह सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके मायने हैं कि देश में गरीबी-रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या नगण्य हो गई है ! लेकिन यह हकीकत नहीं है। बहरहाल 43 करोड़ को 'मुद्रा ऋण' के तहत 22.57 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मुहैया कराए गए हैं। स्वरोजगार के लिए 34 लाख करोड़ रुपए के कर्ज भी दिए गए। इनमें 78 लाख रेहड़ी-पटरी वाले भी हैं, जिन्हें आर्थिक मदद दी गई है। बेशक मोदी सरकार ने किसानों पर खजाने लुटार हैं, लेकिन फिर भी बजट में कहा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार ने कर्ज मुहैया कराए हैं। फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है। दरअसल 'मुद्रा लोन' का घोषित आंकड़ा सवालिया है, क्योंकि पूरे भारत में 26-27 करोड़ परिवार बसते हैं। फिर 43 करोड़ को यह ऋण कैसे दिया जा सकता है ? आंगनवाड़ी बहनों की घोषणा भी सवालिया है। एक तरफ उन सेविकाओं को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता। वे मानदेय के नियमित भुगतान को लेकर अक्सर सड़कों पर प्रदर्शन करने को बाध्य हैं, लेकिन दूसरी ओर उन सभी बहनों को 'आयुष्मान कार्ड' देने की घोषणा की गई है। अंतरिम बजट में 3 रेल कॉरिडोर बनाकर आर्थिक विकास करने की घोषणा की गई है। 'वंदे भारत' में 41,000 रेल डिब्बे शामिल किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बजट में पर्यटन, हरित विकास, प्रदूषणरहित ईंधन, जनसंख्या नियंत्रण व 'स्किल इंडिया' योजनाओं की घोषणा भी है।

राय स्थानांतरणों के मंतव्य

हिमाचल में ताबड़तोड़ तरीके से हो रहे स्थानांतरण के बीच एक गूंज यह कि प्रशासन का निजाम बदल रहा है, दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने सारी स्लैट को साफ करके, लोकतांत्रिक फर्ज को वरीयता दी है। धीरे-धीरे जिलों के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी तथा उपमंडल स्तर तक एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की अदला बदली कर दी है। अधिकारियों की नई पांत बिछा कर सुक़्खु सरकार ने दरअसल अपनी हुकूमत के पते खोले हैं। एक साल की सरकार ने स्थानांतरणों की बड़ी इबारत लिखने से पूर्व संयम बरता और यह आभास नहीं होने दिया कि सत्ता बदलते सभी कुछ बदल गया। इस दौरान ट्रॉसफर हुए जरूर, लेकिन आवश्यकता की परख में ही आदेश हुए। बहरहाल ट्रॉसफर से प्रशासनिक हलिया बदलने की खबर है और यह एक नया इम्तिहान भी है सरकार की नीतियों को सफल बनाने और सुशासन की कलम से नया लिखने का। दरअसल सरकार ने राज्य की व्यवस्था को अपने पैमानों और पहरो के तहत दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है, उम्मीद है यही संदेश विभागीय परतों के परिदृश्य में नए सजावट और नई लिखावट लाएगा। हालांकि ये तमाम स्थानांतरण एक तरह के विशेषाधिकार के तहत सरकार कर रही है, जबकि वर्षों बाद भी न इसकी नीति व नियमों में कुछ नया दर्ज हुआ या पारदर्शिता के साथ 'ट्रॉसफर आर्डर' को विश्वसनीयता से देखा गया। ये तमाम बड़े साहबों के स्थानांतरण हैं, जिन्हें शहरी आवरण में समझा जा सकता है।

बड़े साहबों की कोठियां हर स्थानांतरण के बाद भी सहूलियतों के हिसाब से परिपूर्ण रहती हैं, जबकि कर्मचारियों के ट्रॉसफर का अर्थ विभाग के साथ, राजनीतिक मेलजोल की पारंपरिक रिवायत को निभाते हैं। ग्रामीण स्तर के कार्यालयों, स्कूल-चिकित्सालयों के रिक्त पदों और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा स्तर पर ट्रॉसफर के मानदंड किसी मानक के बजाय एक ऐसी फेहरिस्त में सक्रिय हैं, जो दो कर्मचारियों, दो अध्यापकों, दो डाक्टरों या अन्य पदों पर दो कर्मचारियों- अधिकारियों की आपसी सहमति पर म्यूनुअल धरातल पर अदला-बदली खेलते रहते हैं। हिमाचल में स्थानांतरण के मापदंड साबित करते हैं कि सत्ता में किसी अधिकारी-कर्मचारी का फालक क्या है। अब तो सत्ता के बीच विशेषाधिकार प्राप्त कर्मचारी-अधिकारी भी प्रयाशित तरीके से पदों पर देखे जाते हैं। इसलिए स्थानांतरण से गंतव्य नहीं, मंतव्य साबित होता है। हम जान सकते हैं कि फलों आईएस या एचएस अधिकारी ही क्यों किसी जिला की बागडोर संभाल रहा है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बटालियन में भेजा गया पुलिस अधिकारी क्यों पटरी नहीं बिछा पाया। यही वजह रही है कि पिछली सरकार में एक जिला पुलिस अधिकारी को मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी से उलझते देखकर जनता सहम गई थी। एक यह भी प्रमाण है कि सारे अधिकारी अब व्यवस्था में 'अपनी-अपनी' सरकार खोज रहे हैं। प्रशासन के तत्व, राजनीतिक पहुंच के अंग शून्य हो सकते हैं, लेकिन वीआईपी कारवां जब चलता है तो यह सफर अब नेताओं को नायक और अधिकारियों के हुजूम को तलवे चाटता देखाता है। होते हैं कभी कुछ कड़क पुलिस अधिकारी जो अपराध को खींच लाते हैं बाहर या नशे के सौदागरों को जमीन पर सुला देते हैं, लेकिन अधिकांश कानून व्यवस्था को बदनाम नहीं करते। ऐसे भी एसएचओ स्तर के अधिकारी कामयाब हो जाते, जो जुर्म के पत्नों को खारिज करके सिर्फ ट्रैफिक चालान के पर्याय बन जाते हैं।

भूपिंदर सिंह

खिलाडी को तैयार करने में प्रशिक्षक की भूमिका जब जरूरी है तो फिर हम उसे सामाजिक–आर्थिक रूप से निश्चित कर प्रशिक्षण पर केन्द्रित क्यों नहीं होने देते•

राज्य में खेल विभाग बनने के बाद आज तक कई सरकारें आईं, मगर खेल विभाग के हाल नहीं सुधरे हैं। दशकों से हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षकों से अन्याय हो रहा है। कहा गया कि प्रशिक्षक कैडर के भर्ती व पदोन्नति नियमों में सुधार कर लिया है, मगर अभी तक जूनियर प्रशिक्षक का स्केल और काम जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी का लिया जा रहा है। इस विषय पर इस कॉलम के माध्यम से बार–बार सरकार को चेताया कि राज्य में प्रशिक्षकों का स्तर ऊंचा किए बिना खेलों में उत्कृष्टता हासिल नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी करोड़ों लोगों में स्वयं व अपने देश को पदक जीत कर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है तो उसके पीछे जहां उस दृढ़ संकल्प, लगातार कठोर परिश्रम व अपनों की सहायता व दुआएं होती हैं, वहीं पर एक प्रशिक्षक की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अलग से राज्यों में खेल विभागों का गठन हुआ है। 1982 के एशियाड के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का गठन किया। विभाग के गठन के चार दशक बाद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षकों के भर्ती व पदोन्नति नियमों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है।

हिमाचल प्रदेश के इस विभाग में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों, कनिष्ठ प्रशिक्षकों व युवा संयोजकों के पद सृजित हैं। इस विभाग का कार्य प्रदेश में युवा

गतिविधियों व खेलों का विकास करना है। हिमाचल प्रदेश में यह विभाग खेल प्रशिक्षण, खेलों के लिए आधारभूत ढांचा व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता होने पर नगद पुरस्कार व अवार्ड देने के लिए बनाया गया है।

हिमाचल प्रदेश के इस विभाग का निदेशक प्रशासनिक सेवा से ही अधिकतर नियुक्त होता रहा है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही आज तक दो बार ही विभागीय अधिकारी निदेशक पद तक पहुंच पाए हैं। उपनिदेशक और कभी–कभी संयुक्त निदेशक पद तक विभाग के प्रशिक्षक व युवा संयोजक पदोन्नत होकर पहुंच जाते हैं। इन विभागीय अधिकारियों को अधिक तकनीकी जानकारी होती है। आजकल हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के पास कोई भी उपनिदेशक नहीं है। वरिष्ठ जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को उपनिदेशक के पद पर बिठा कर काम चलाया जा रहा है। निर्यात जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी भी केवल कुछ ही जिलों में हैं, शेष जिलों में कामचलाऊ अधिकारी बिठा रखे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही उपनिदेशक के पद पर नियमित पदोन्नति की जाए तथा जिलों में भी नियमित अधिकारी हों। इस समय जो प्रशिक्षक जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद पर तैयारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें एकमूर्त नियमों में दृष्ट देकर नियमित अधिकारी बना दिया जाए। इस विषय पर पहले भी इस कॉलम के माध्यम से लिखा जा चुका है, मगर लगता है कि सरकार के लिए युवा शक्ति व जनक प्रार्थमिकता पर नहीं हैं। विभाग में नाममात्र के प्रशिक्षक हैं। अधिकतर खेलों में तो एक भी प्रशिक्षक पूरे जिले के लिए उपलब्ध नहीं है। विभाग में जो प्रशिक्षक नियुक्त हैं उन्हें कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। उसके बाद वे सेवानिवृत्ति तक भी प्रशिक्षक नहीं बन पाए हैं।

विभाग में नियुक्त प्रशिक्षकों को जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी पद पर पदोन्नति के

प्रशिक्षकों के साथ अन्याय क्यों ?



लिए केवल 25 प्रतिशत ही कोटा है। 150 प्रतिशत युवा संयोजक व 25 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। प्रशिक्षक बनने की योग्यता बहुत कठिन है। स्नातक डिग्री के साथ जो प्रतिभागी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो या तीन बार वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हुआ हो या शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेला हो, उसके बाद राष्ट्रीय क्रिडा संस्थान में प्रवेश परीक्षा पास कर एक वर्ष के जूनियर प्रशिक्षण व शिक्षण के बाद प्रशिक्षक बनता है। सेवा नियमों में एक समय एमपीएड के साथ कैंडस कोर्स, जो छह माह का होता था, उसे पास किया हुआ प्रशिक्षक के पद के लिए योग्य था, मगर अब ऐसा कोई नियम नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश में नियुक्त कनिष्ठ प्रशिक्षकों को पांच साल के बाद प्रशिक्षक के पद पर पदोन्नत कर 50 प्रतिशत कोटा जिला अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए

दिया जाए, क्योंकि प्रशिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। अगर हर खेल में जिला स्तर पर पांच प्रशिक्षक भी हों तो प्रशिक्षकों की संख्या सौ से भी अधिक जा सकती है। इसके मुकाबले बारह जिलों में बारह ही युवा संयोजक नियुक्त हैं। इस तरह देखा जाए तो यह प्रशिक्षकों के साथ बहुत अन्याय है। प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तो बन कर तैयार हैं, मगर उनका न तो सही रखरखाव है और न ही उन पर उस स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है।

सरकार को चाहिए कि वहां पर उन खेलों में उच्च प्रदर्शन करवाने वाली खेल अकादमियां स्थापित की जाएं। हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के दो खेल छात्रावास विलासपुर व ऊना में कुछ चुनिंदा खेलों के लिए कामचलाऊ प्रशिक्षण प्रबंध तो हैं, मगर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों की कमी व प्रबंधन में अव्यवस्था साफ देखी जा सकती है। उत्कृष्ट खेल प्रतिष्ठाम दिलाने वाले प्रशिक्षक

बहुत कम हैं। क्योंकि विभाग में प्रशिक्षकों की अनदेखी जिसमें बहुत कम ग्रेड पै व दशकों से कनिष्ठ पद पद पर कार्यरत रहने के कारण राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान से प्रशिक्षी प्रशिक्षक खेल विभाग में प्रशिक्षक बनने से अधिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक या डीपीई बनने को अधिमान देते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए प्रशिक्षकों व खिलाडिटर के लिए एक अच्छी प्रशिक्षण टीम की अहम भूमिका है। सही प्रबंधन मिले, इसके लिए नियमित जिला खेल अधिकारियों, उपनिदेशकों, प्रशिक्षकों, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। खिलाड़ी को तैयार करने में प्रशिक्षक की भूमिका जब बेहद जरूरी है तो फिर हम उसे सामाजिक व आर्थिक रूप से निश्चित कर शारीरिक व मानसिक पूरी तरह अपने प्रशिक्षण पर केन्द्रित क्यों नहीं होने देते। इसलिए राज्य के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में प्रशिक्षकों के साथ न्याय करने के लिए इनके भर्ती व पदोन्नति नियमों में संख्या अनुपात में संशोधन करना बहुत जरूरी है।

हास्य रस

परतंत्र भारत में लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों से साफ शब्दों में कहा था कि 'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा।' इसके बदले मिली उनकी असंख्य यादनाएं और जेल यात्राओं की अनवरत त्रासदियां। लेकिन वे अपनी बात से अंतिम समय तक नहीं हटे तथा आजादी की अलख को जलाए रखा। उस समय ऐसे ही नेताओं की भरमार थी, जो भारत माता को परतंत्रता की बेडियों से मुक्त कराने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्हें अपने देश से असौम प्रेम था। आज का नेता भी इस मामले में कहां कम है। बस उस समय आजादी की चाहना थी और आज कुर्सी की। आज के नेता का यही कथन है कि कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध

अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पहले भारत के लिए पर मिलने की तमन्ना थी और अब कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने की लालसा है। बस चाहनाएं बदली हैं, बाकी नेताजी उस समय के नेताओं से कहां पीछे हैं। कुर्सी पर जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब नेताजी का इस बात से है कि अब राजनीति में वंशवाद की विषबेल तेजी से फल-फूल रही है। नेता का बेटा नेता ही बनता है, वह कोई दूसरा व्यवसाय या धंधा नहीं अपनाता। हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्हें अपने देश से असौम प्रेम था। आज का नेता भी इस मामले में कहां कम है। बस उस समय आजादी की चाहना थी और आज कुर्सी की। आज के नेता का यही कथन है कि कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध

कि उनके पिताजी, काकाजी या जीजाजी ने पोजीशन ले ली है, उसके आधार पर वे सीधे ही सांसद या विधायक का टिकट प्राप्त कर लेते हैं। टिकट मिलने के बाद कुर्सी कोई ज्यादा दूर नहीं रहती। कुर्सी चलकर उनके पास आ जाती है। जब कुर्सी आ जाती है तो वे कुछ भी अवैध कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र भारत में रहकर राजनीति का धंधा कर रहे हैं। कुर्सी की प्राप्ति के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, करते हैं। पता नहीं कितनी बार दल बदलते हैं। यही अवसरवादिता तो उन्हें कुर्सी दिलवाती है। चुनाव जीतने के लिए साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता तथा भाषावाद, जिसकी भी आवश्यकता है, उसका आस लेते हैं। नए-नए

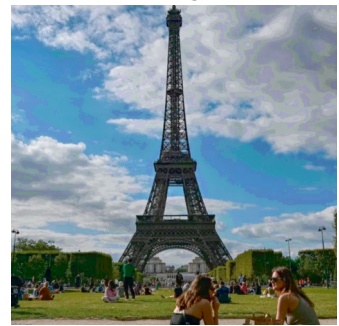
गठबंधन, नए से नए गठजोड़ और तालमेल तथा नए से नया समीकरण कुर्सी हथियाने के पुर हैं। राजनीति में जो जितना गिरता है, वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। चुनाव जीतने के जितने भी तरीके हैं, उनके लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है, नेताजी इसके लिए घोटालों पर घोटाले करते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार उनके दोनों हाथों का नायाब खेल है। जांच आयोग बैठ जाए तो नेताजी के कैरियर में चार चांद लग जाते हैं। वे बारबार सुर्खियों में बने रहकर अपनी प्रतिभा के तेज से जनमानस की आंखों को चुंधियाते रहते हैं। क्योंकि पहली बात तो जांच आयोग की रिपोर्ट वर्षों तक आती नहीं और मामले न्यायालयों में लम्बित चलते रहते हैं और यदि रिपोर्ट आ भी

जाती है तो वह टाय-टाय फिक्स होती है। उसमें नेताजी साक्ष्यों के अभावों में बेगम और निर्दोष पाए जाते हैं। जितने भी मामले अब तक हुए हैं, उन पर दृष्टिपात कर देख लीजिए। किसी नेता का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर नेता गंजे होते हैं। गंजे पर शर्म का पानी ठहरता नहीं, चाहे चीनी, चारा, यूरिया, बोफोर्स या हवाला का मामला बनाम घोटाला हो, तमाम नेता देश के कर्णधार बने हुए हैं। अग्रिम बेल मिल जाती है और उनकी कुर्सी ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि कुर्सी उनके जन्मसिद्ध अधिकार में सम्मिलित है, तो वह बला छीनी भी कैसे जा सकती है।

पूरन सरमा

इनसाइड

अब एफिल टॉवर घूमना होगा और भी आसान, UPI पेमेंट के जरिए कर सकेंगे टिकट बुक



भारतीय अब पेरिस के एफिल टॉवर देखने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके टिकट बुक कर सकेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स (NIPL) ने फ्रेंच ई-कॉमर्स और प्रोक्सिमिटी पेमेंट्स लायरा के साथ साझेदारी की है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यूरोपीय देश में यूपीआई भुगतान तंत्र स्वीकार किया जाए। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुंबई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि पेरिस के एफिल टॉवर देखने आने वाले पर्यटक अब भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके प्रतिष्ठित स्मारक की अपनी यात्रा बुक कर सकेंगे। एनपीसीआई ने कहा कि उसकी शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स (NIPL) ने फ्रेंच ई-कॉमर्स और प्रोक्सिमिटी पेमेंट्स लायरा के साथ साझेदारी की है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यूरोपीय देश में यूपीआई भुगतान तंत्र स्वीकार किया जाए।

UPI के जरिए खरीद सकेंगे टिकट एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय पर्यटक अब यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करके ऑनलाइन टिकट खरीदकर एफिल टॉवर की अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं, जिससे लेनदेन प्रक्रिया त्वरित, आसान और परेशानी मुक्त हो जाएगी। आपको बता दें कि यह घोषणा भारत के गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए फ्रांस में भारतीय दूतावास द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी।

इसमें कहा गया है कि वर्तमान में, भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के दूसरे सबसे बड़े समूह में हैं। भारतीय पर्यटक बस वेबसाइट पर जनरेट क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं।

एफिल टॉवर फ्रांस में यूपीआई भुगतान की पेशकश करने वाला पहला बिजनेस है, और यह सेवा जल्द ही फ्रांस और यूरोप में पर्यटन और खुदरा क्षेत्र के अन्य बिजनेस तक विस्तारित की जाएगी।

क्यों किया गई ये पहल एनआईपीएल के मुख्य कार्यकारी रिशेश शुक्ला ने कहा कि ये यूनिट एक इंटरऑपरेबल वैश्विक भुगतान प्रणाली बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एनपीसीआई के भुगतान समाधानों की स्वीकृति को सक्षम करने की इच्छा रखती है।

ग्राहकों के गिरते भरोसे को थामने में जुटा पेटीएम, 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा पेटीएम ऐप

आरबीआई की ओर से 29 फरवरी के बाद नये ग्राहक जोड़ने ग्राहकों की तरफ से नई राशि स्वीकार करने प्रीपेड भुगतान के लिए इस्तेमाल में लाये जाने या फास्टटैग में इस्तेमाल पर रोक के निर्देश के बाद मुसीबत में फंसे पेटीएम ने ग्राहकों को सबकुछ सामान्य होने का भरोसा दिया है। फिलहाल पेटीएम को लेकर अविश्वास इतना है कि लोगों ने इसके ऐप को डिलीट करना शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। नियमों के अनुपालन में कोताही के कारण आरबीआई की ओर से 29 फरवरी के बाद नये ग्राहक जोड़ने, ग्राहकों की तरफ से नई राशि स्वीकार करने, प्रीपेड भुगतान के लिए इस्तेमाल में लाये जाने या फास्टटैग में इस्तेमाल पर रोक के निर्देश के बाद मुसीबत में फंसे पेटीएम ने ग्राहकों को सबकुछ सामान्य होने का भरोसा दिया है। यह और बात है कि निवेशकों से लेकर ग्राहकों तक में फिलहाल पेटीएम को लेकर



अंतरिम बजट में सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। सरकार के प्रयास से पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए 80671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

नई दिल्ली। बहुआयामी गरीबी से देश की

सभी जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार का प्रयास अंतरिम बजट में भी दिखा। अंतरिम बजट में सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं।

पोषण, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं का स्वास्थ्य, स्कूल में बिताए जाने वाले साल, स्कूल में बच्चों की हाजिरी, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, आवास, संपदा व बैंक खातों सुविधाओं के आधार पर

बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है। ये ऐसी सुविधाएँ हैं जिसे मिलने से लोग खुद को गरीब नहीं समझते हैं। भले ही उनकी नकद आय नहीं बढ़ी हो।

नौ सालों में 24.82 करोड़ दायरे से बाहर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयास से पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है। अब भी 15 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार हैं। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गत

गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में बहुआयामी गरीबी से जुड़े मानकों में सबसे अधिक 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी आवास के मद में की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए 80671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुताबिक इस मद में 54103 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 12467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में संशोधित

अनुमान के मुताबिक इस मद में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

LPG कनेक्शन के लिए 9094 करोड़ रुपए खर्च गरीब परिवारों के एलपीजी कनेक्शन के लिए आगामी वित्त वर्ष में 9094 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 8500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छता के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 7192 करोड़ का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 7000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश अगले दो साल में 10 करोड़ तक जा सकता है ITR का आंकड़ा

Income Tax

इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ है जो अगले वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ है जो अगले वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

किए जा सकते हैं बदलाव बजट में मैनुफैक्चरिंग से जुड़े कई आइटम में वस्तुओं के आयात शुल्क में उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं

होने के बारे में पूछे जाने पर राजस्व सचिव ने कहा कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में वस्तुओं के आयात शुल्क में जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जा

सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट से ठीक एक दिन पहले ही हमने मोबाइल फोन के पार्ट्स के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की थी।

चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया का उज्ज्वल स्थान बना रहेगा: पीयूष गोयल



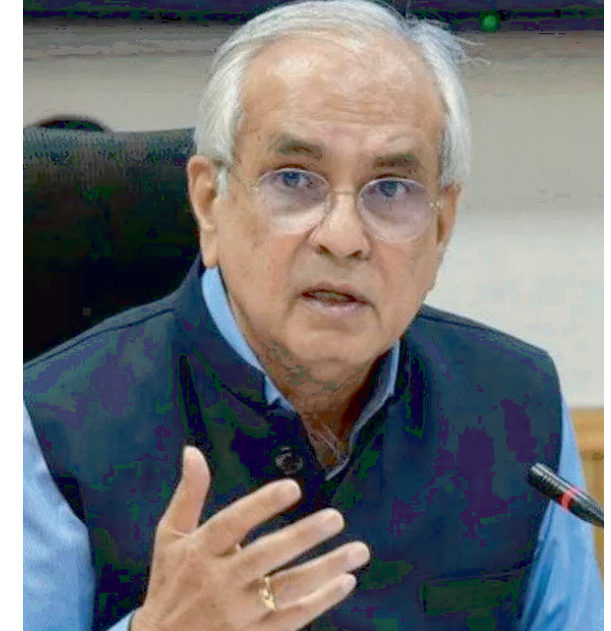
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि एफटीए करते समय सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी शर्तें भारत के लिए सर्वोत्तम हों। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रभावित किया है लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत विदेशी कंपनियों के लिए दुनिया का उज्ज्वल स्थान बना रहेगा। गोयल ने कहा

लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत विदेशी कंपनियों के लिए दुनिया का उज्ज्वल स्थान बना रहेगा।

गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) या द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर करते समय सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि सभी शर्तें भारत के लिए सर्वोत्तम हों। गोयल ने कहा, 'वैश्विक अनिश्चितता ने निश्चित रूप से एफडीआई को प्रभावित किया है, खासकर यह देखते हुए कि अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में ब्याज दरों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखी गई है। मंत्री ने कहा कि भारत की आकांक्षी आबादी और अन्य समर्थक हमें यह विश्वास दिला रहे हैं कि सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत वृद्धि करना जारी रखेगा।' स्टार्टअप के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव के प्रभाव पर पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि इसका मुकसद देश के स्टार्टअप परिवेश को प्रोत्साहित करना है।

कर या आयात शुल्क में बदलाव न करने के वित्त मंत्री के फैसले पर गोयल ने कहा, 'यह उचित है कि उन्होंने रियायतें देने या दरों में कोई बदलाव करने के प्रलोभन से खुद को दूर रखा है।

राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ वाला है अंतरिम बजट: बेरी



नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले सरकार वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। सुमन बेरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनाव-पूर्व अंतरिम बजट को राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल के बजट का राजकोषीय परिणाम अनुमान से बेहतर है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनाव-पूर्व अंतरिम बजट को 'राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ' वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। बेरी ने कहा कि अंतरिम बजट एक नया आधार तैयार करता है और जुलाई में पेश किए जाने पूर्ण बजट के बारे में संकेत देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि

इस साल के बजट का राजकोषीय परिणाम अनुमान से बेहतर है। उन्होंने कहा, 'हम 2025-26 के लिए 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि यह सार और संकेत दोनों ही नजरिये से अहम हैं।' सरकार ने अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत तक लाने की संशा जताई है।

निजी निवेश दोबारा शुरू होने के संकेत बेरी ने कहा कि निजी निवेश दोबारा शुरू होने के कई संकेत दिख रहे हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई थी, लिहाजा पूंजीगत व्यय पर जोर दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि बजट में घोषित उपाय अधिक नौकरियाँ पैदा करने में किस तरह मददगार होंगे, उन्होंने कहा कि मुद्दा नौकरी नहीं है, मुद्दा अच्छी नौकरियाँ हैं। भारत में नौकरियों के अनुरूप कर्मचारियों का मिलना मुश्किल हो रहा है।' उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रक्रियागत सुधार मुश्किल हैं जिनमें से कुछ को राज्यों के स्तर पर अंजाम देना है।

10वीं में 10 तो 12वीं में छह विषयों में पास होना जरूरी

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। नए सत्र से नौवीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। एनसीआरएफ के तहत क्रेडिट गणना के लिए 30 शिक्षण घंटों को एक क्रेडिट के रूप में गिना जाएगा। विद्यार्थियों की एक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में गतिशीलता और आमूल चूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक विषयों और कौशल विषयों में क्रेडिट देना शामिल है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति ने स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक एक प्रकीकृत क्रेडिट संंचय और हस्तांतरण ढांचा तैयार किया।

10वीं में विद्यार्थियों को पढ़ने होंगे 10 विषय

इसके तहत सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और एनआईओएस बोर्ड से संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को लागू करने के लिए दिशानिर्देश (एसओपी) विकसित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। नए सत्र से नौवीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा।

वहीं 12वीं में विद्यार्थियों को कुल छह विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। अब तक विद्यार्थी 10वीं में अधिकतम नौ विषय चुन सकते थे, लेकिन वे छह विषय ही चुनते थे और पास होने के लिए पांच विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। वहीं 12वीं में कोई विद्यार्थी सात विषय चुन सकता था, जिसमें एक वैकल्पिक होता था। इसमें से विद्यार्थी को पांच विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था।

10वीं में होंगी अब तीन भाषाएं

अब 10वीं कक्षा में तीन भाषाएं शामिल होंगी, जिसमें दो भाषा कम से कम भारत में बोली जाने वाली होंगी, वहीं सात मुख्य विषय होंगे। इसमें गणित व



कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा और अंतः-विषय क्षेत्र शामिल हैं। विद्यार्थी को सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

12वीं में दो भाषा विषय होंगे शामिल

12वीं में अब विद्यार्थियों को एक के बजाय दो भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें कम से कम एक भाषा भारत में बोली जाने वाली होगी, वहीं चार मुख्य विषय और एक वैकल्पिक विषय होगा। यह सभी विद्यार्थियों को चयनित करने होंगे। एनसीएफ के तहत इन विषयों को तीन समूह में बांटा गया है। जिसमें से विद्यार्थियों को किसी दो समूह से चार विषय चयनित करने होंगे। पहले समूह में संगीत, नृत्य, थिएटर, स्कल्पचर, पें ``टग, शारीरिक शिक्षा और कल्याण व व्यावसायिक शिक्षा शामिल है।

दूसरे समूह में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, वाणिज्य व पर्यावरण शिक्षा शामिल है। तीसरे समूह में गणित, प्रोग्रॅमिंग व कोडिंग, बिजनेस गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान शामिल है।

मुख्य बिंदु

क्रेडिट के आवंटन के लिए कुल अनुमानित 1200 शिक्षण घंटे प्रति वर्ष होंगे, जिसके लिए 40 क्रेडिट दिए जाएंगे।

विद्यार्थियों को एक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी। मुख्य परीक्षाओं में क्रेडिट, विद्यार्थियों के ग्रेड कार्ड में अंकों और ग्रेड के साथ दर्शाया जाएगा। अर्जित क्रेडिट विद्यार्थी के अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में जमा किया जाएगा जो छात्र के डिजिटलाकर से जुड़ा होगा।

प्रत्येक विषय सात क्रेडिट का होगा, एक सत्र में 210 घंटे आवंटित किए गए हैं।

प्रत्येक अध्याय के लिए घंटे आवंटित हैं और इसे आगे सैद्धांतिक और व्यावहारिक घंटों में विभाजित किया गया है।

क्रेडिट की गणना

एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे के शिक्षण या दो घंटे के व्यावहारिक कार्य क्षेत्र कार्य के बराबर होगा। एक क्रेडिट का मतलब 15 घंटे के सिद्धांत (थ्योरी) या 30 घंटे का कार्यशाला या प्रयोगशाला कार्य के बराबर होगा।

इलाहाबाद-राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति, जानिए किसको कहाँ मिली जिम्मेदारी

इलाहाबाद और राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई। इन सभी न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश गत दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्तियों की घोषणा एक्स पोस्ट में की। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। इलाहाबाद और राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई। इन सभी न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश गत दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्तियों की घोषणा एक्स पोस्ट में की। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायाधीश बाहरी के उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद देश के 25 हाई कोर्ट में से दो का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं।

अब सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने की अनुमति नहीं दे सकेगी पंचायतें

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने परिपत्र जारी कर बताया कि सरकारी बिलानाम अथवा चारागाह भूमि से मिट्टी उठाने हेतु कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा बिना किसी अधिकार के कतिपय व्यक्तियों या फर्मों को अनुमति अथवा अनापत्ति जारी कर दी जाती है

एवं इस हेतु राशि भी संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करायी जाती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार आबादी भूमि तक ही सीमित है, किसी भी राजकीय बिलानाम एवं चारागाह भूमि का स्वामित्व केवल राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार का ही है। इसलिए

ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय भूमि से मिट्टी दोहन की दी गई अनुमति अनाधिकृत एवं अवैध है, ऐसी समस्त अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि पूर्व में दी गई ऐसी अनुमतियों या अनापत्तियों के बदले प्राप्त राशि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा तहसील कार्यालय में राजस्व मद

0029 में जमा कराई जाए। जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने निर्देशित कर कहा कि समस्त पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचों को इस आदेश की प्रति पालना हेतु प्रेषित की जाकर उनसे रसीद प्राप्त कर रेकार्ड पर रखी जाए। साथ ही भविष्य में यदि संबंधित ग्राम पंचायतों



तेलंगाना इवेंट ऑर्गनाइजेशन का 15वां नर्सरी मेला आज से हैदराबाद में

ब्यूरो चीफ जगदीश सीरवी

तेलंगाना। इवेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में 15वां भव्य नर्सरी मेला का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय स्तर के नर्सरी मेला का शुभारंभ 1 फरवरी को यानी आज प्रदेश के कृषि मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव के हाथों। पौधों और फूलों से सजे भव्य द्वाड़/गांवल में हुआ। पांच दिनों तक चलने वाले इस नर्सरी मेला का समापन 5 फरवरी को होगा। मिली जानकारों के अनुसार, सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक चलने वाले में देशभर से 140 से ज्यादा व्यापारी अपने स्टॉल लगा रहे हैं। पुणे, बेंगलुरु, तेलंगाना और आंध्र

प्रदेश सहित अन्य हिस्सों से आए व्यापारियों ने अपने स्टॉल यहां लगाए हैं जिसमें उपरोक्त के अलावा मुंबई, दिल्ली, समेत कई शहरों के नर्सरी प्रेमी भाग लेंगे।

इस नर्सरी मेला के निदेशक खालिद अहमद जमीर ने नर्सरी टुडे को बताया कि इस मेले में 140 से अधिक स्टॉल पर अनेक प्रकार के फूल-पौधे आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां ओरिएंटल लिली, हाईब्रिड डच रलैडुलर, ऑर्किड, विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप और गुलाब जैसे फूलों के पौधों की कई किस्मों का प्रदर्शन किया जा जा रहा है।

वहीं ग्रोमोर फूड नर्सरी के

संचालक प्रवीण सत्यार्थी ने कहा कि इस नर्सरी मेला से दर्शकों को उम्मीद है कि यहां पौधों, फूलों और सज्जियों के बीजों से लेकर पर्यावरण-अनुकूल बागवानी उत्पाद मेले में देखने को मिलेंगे।

नर्सरी मेला में मिलेंगे बोनसाई पौधे

नर्सरी मेला में जगह-जगह कई ट्रे ट्रीच / बोनसाई स्टूडियोज़ द्वारा स्थापित बोनसाई पौधे का स्टाल पौधे प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। स्टॉल में अलग-अलग कीमती के विभिन्न बोनसाई पेड़ रहेंगे। इस मेले में घर की छत पर लगाने वाले बागवानी के पौधे भी रहेंगे। यहां गमले के अलावा पौधों में डालने वाले

उर्वरक भी मिलेंगे। इसके अलावा इस मेले में गमले, कोको बर्तन, बोन्साई लगाने के लिए बड़े गमले भी मिलेंगे।

गार्डन फर्नीचर भी मिलेंगे

सत्यार्थी ने बताया कि नर्सरी मेला में रंग-बिरंगे फूलों-पौधों के अलावा लोग गार्डन फर्नीचर की भी खरीदारी कर सकते हैं। गार्डन फर्नीचर के अलावा सौंदर्य आकर्षण से गार्डन की शोभा बढ़ाने वाली लाइट भी इस मेले में मिलेगी। गार्डन लाइट लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। गार्डन लाइट से आप अपने घर के आसपास के गार्डन का डिजाइन कर सकते हैं। यह गार्डन की खूबसूरती में चारचांद लगाने का एक अच्छा ऑप्शन है।

तेलंगाना में 8 फरवरी को छुट्टी घोषित

गई है। लेकिन फरवरी में कोई नियमित छुट्टीयां नहीं हैं। आम त्योहार मार्च के बाद जनवरी में आते हैं। सरकार की ओर से जारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च को माह शिवरात्रि के मौके पर छुट्टी है। 25 मार्च को होली का दिन है। 29 मार्च को गुड फ्राइडे के मौके पर छुट्टी दी गई थी। 15 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। 19 अप्रैल को उगादी की छुट्टी है। 11 और 12 अप्रैल को रमजान की छुट्टी घोषित की गई। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को श्री राम नवमी की छुट्टी भी दी गई है। 17 जुन को बकरीद की छुट्टी है। 17 जुलाई को मेहमार की छुट्टी, 29 जुलाई को बोनालों के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। 15



अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छुट्टी गई है। 17 सितंबर को गणेश चतुर्थी का दिन है। 16 सितंबर को ईद नबी की छुट्टी दी गई थी। 12 अक्टूबर को माहात्मा गांधी जयंती, 12 और 13 अक्टूबर को दशहरा, 31 अक्टूबर को दिवाली, नवंबर को गुरु नानक जयंती, 25 और 26 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी घोषित की गई।

लकपति दीदी कहाँ हैं? कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओइशि

भुवनेस्वर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024-25 का मसौदा पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन कांग्रेस की शिकायत है कि आम लोगों को लाभ देने के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि इस बजट पर ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पंचानन कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी है। लकपति दीदी कहाँ हैं?



श्रीमती केसरबाई सोनी की 34 वी पुण्यतिथि पर संगम विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में श्रीमती केसरबाई सोनी की 34 वी पुण्यतिथि पर संगम विश्वविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस एवं सोशल क्लब के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया रक्तदान शिविर संयोजक लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुराग सोनी द्वारा किया गया। संगम विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्राही, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर राजीव मेहता, चीफ फाइनैस अकाउंट ऑफिसर सतीश यादव, डेप्युटी रजिस्ट्रार अनुराग शर्मा आदि के द्वारा सभी रक्त दाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने सभी रक्तदाताओं तथा सफल आयोजन के लिए टीम सदस्यों को बधाई दी लिफ्टीनेंट राजकुमार जैन ने बताया की कुल 58 यूनिट का रक्तदान किया गया तथा जिसके सहयोग हेतु अरिहंत हॉस्पिटल के मेडिकल टीम सदस्य, एचआर सुरेश सिंह, एनसीसी, एनएसएस आदि का धन्यवाद दिया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18, 19, 20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, ग्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सर्म्फ : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023